भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की लाभदायकता और वित्तीय निष्पादन क्षमता पर बासेल II के प्रभावों (पूर्व एवं पश्चात्) का विश्लेषण

[भारत में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैकों का एक तुलनात्मक अध्ययन]

An Analysis the Impact (Pre and Post) of Basel II on the Profitability and Financial Performance of Indian Banking Sector.

[A Comparative Study of Public and Private Sector Banks in India.]

शोध प्रस्ताव

लेखा एवं विधि विभाग

(वाणिज्य संकाय)

निर्देशक

डॉ. लक्ष्मीनारायण कोली

(एसोसिएट प्रोफेसर)

शोध छात्र

अमित सिंह

लेखा एवं विधि विभाग

वाणिज्य संकाय, दयालबाग शिक्षण संस्थान

(डीम्ड विश्वविद्यालय)

आगरा-5

शोध रूपरेखा की विषय सूची
Contents of Synopsis

	पृष्ठ संख्या
1. विषय प्रवेश (Introduction)	1 - 6
2. साहित्यिक पुर्निरीक्षण (Review of Literature)	7 - 10
3. प्रस्तावित शोध अध्ययन के महत्व (Significance of Proposed Research Study)	11 - 11
4. प्रस्तावित शोध अध्ययन के उद्देश्य (Objectives of Proposed Research Study)	11 - 11
5. प्रस्तावित शोध अध्ययन की शोध परिकल्पना (Research Hypothesis of Proposed Research Study)	12 - 12
6. प्रस्तावित शोध अध्ययन की कार्यविधि (Methodology of the Proposed Research Study)	13 - 14
7. प्रस्तावित शोध अध्ययन की अवधि (Period of Proposed Research Study)	14 - 14
8. उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए रूपरेखा (Proposed action plan to achieve Objectives)	15 - 15
9. प्रस्तावित शोध अध्ययन की विषय सूची (Contents of Proposed Research Study)	16 - 17
9. सन्दर्भ सूची (References List)	18 - 21

.

शोध रूपरेखा (SYNOPSIS)

विषय प्रवेश (Introduction)

भारत तेजी से एक मजबूत अर्थव्यवस्था और एक वैश्विक शक्ति के रूप में दुनिया के नक्शे पर उभर रहा है। भारत देश तेजी से विकास की सीढ़ियां चढ़ रहा है। देश ने सभी महत्वपूर्ण उद्योगों और क्षेत्रों में वृद्धि दर्ज की है। जिस कारण निवेशक भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

बैकिग एक बहुत प्राचीन व्यवसाय है। प्राचीन काल में आज के समय जैसे आधुनिक बैंक तो नही थे, परन्तु बैंकिग का कार्य महाजनों, साहूकारों और सर्राफों के द्वारा सभी देशों में किया जाता था। इसा से 2000 वर्ष पहले बेबीलोन में साख का लेन – देन प्रचलित था। भारत में भी वैदिक काल से बैंका के होने का अनुमान लगाया जाता है। बैंकिग मात्र ऋण देने से कुछ अलग ह। वास्तव में यह कहीं अधिक से अधिक परिष्कृत और जटिल है। विकासशील अथव्यवस्था को तुलना में अधिक से अधिक रचनात्मक और उद्देश्यपूर्ण है।

भारत में बैंकिग तृतीयक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह हमारी आर्थिक प्रगति और समृद्धि की रीढ़ की हड्डी क रूप में कार्य करता है। यह विकास में एक उत्प्रेरण की सभी व्यापक भूमिका निभाता है। पिछले एक दशक में भारतीय बैंकिग क्षेत्र में कई सकारात्मक प्रगति देखी गयी है।

आधुनिक बैंकिग का प्रारम्भ सबसे पहले यूरोप में हुआ था, जबकि इटली में 1171 में बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना हुई। इसके बाद अनेक बैंक स्थापित हुए जिनम 1401 म बक ऑफ बारसीलोन, 1607 में बैंक ऑफ जेनेवा , 1609 में बैंक ऑफ एमस्टर्डम, 1619 में बैंक ऑफ हैमबर्ग और 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैण्ड के नाम उल्लेखनीय ह। परन्त् वाणिज्य बैंको का विकास 19 वीं शताब्दी के मध्य तक विशेष रूप से सम्भव नही हो पाया। इंग्लैण्ड में 1833 ई . के बैंकिग अधिनियम के निमार्ण के पश्चात ही संयुक्त पूँजी वाले बैंको की स्थापना तथा विकास हुआ। आधुनिक समय में बैंक प्रणाली व व्यापार व्यवस्था के अविभाज्य अंग बन गये ह।

भारतीय मुद्रा बाजार में रिजर्व बैंक को कन्द्रीय स्थान प्राप्त है क्योंकि वही देश में साख का नियमन व नियंत्रण का कार्य करता है। भारतीय मुद्रा बाजार को प्राय: दो भागों में विभाजित किया जा सकता है – संगठित क्षेत्र एव

असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र में स्टेट बैंक, उसके 7 अनुषंगी बैंक, 19 राष्ट्रीय कृत, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी व गैर -सहकारी क्षेत्र के अन्य बैंक सम्मिलित किए जाते है, जबकि असंगठित क्षेत्र में साहूकार, महाजन आदि आते है।

Bruisers के समय के दौरान, तीन प्रेसीडेसी बैंक, बंगाल (1809), मुंबई (1840), और मद्रास (1843) मे खोले गये। बैंकिग संकट के कारण 27 जनवरी 1921 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तीनों प्रेसीडेसी बैंको का इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया में विलय कर दिया गया।

बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेट (Bank of International Settlement)

विश्व की सबसे पुरानी अंतराष्ट्रीय वित्तीय संस्था बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेट की स्थापना 17 मई 1930 को हुई थी। यह संस्था केन्द्रीय बैंको के सहयोग के मुख्य केन्द्र के रूप मे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी स्थापना उस ''यंग योजना'' (1930) के अन्तर्गत की गई थी, जिसके माध्यम से प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुइ बर्साय की संधि के पश्चात् जर्मनी पर लगाए गए हर्जाने की राशि के भुगतान के मुद्दे को निपटाया जा सके। ''यंग योजना'' के माध्यम से बैक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेट को यह निर्देश दिया गया था कि वह जर्मनी पर लगाए गए हरजाने के भुगतानों का प्रबंधन करे। छ: देशों बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनो, इटली, स्विट्जरलैंड तथा अमेरिका के केंद्रीय बैंको द्वारा इसे निधि प्रदान की गई तथा इसके कार्यालय स्थल के लिए स्विट्जरलैंड के बासल शहर को चुना गया। बैंकिग पर्यवेक्षण पर बासले समिति G10 के सदस्य देशों के बैंक पर्यवेक्षकों को मिलाकर बनाई गई एक समिति है जो सदस्य देशों के कन्द्रीय बैंक के गवनंरों के प्रतिनिधित्व में अपना कार्य करतो है। समिति के सदस्य बेल्जियम, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, स्पेन, जापान, नीदरलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, स्वीडन, इटली, लक्समबर्ग है।

1930 से बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेट म केन्दीय बैका, सहयोगी केन्दोय बैका के गवनरा तथा अन्य संस्थाआ के विशेषज्ञा की बासेल में नियमित बैठकें होती रही ह। समय बीतने के साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था और वश्विक बैंकिग क्षेत्र में बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेट की भूमिका महत्वपूर्ण और बेहतर होती चली गई।

1970 के दशक म अतंराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों के विकास और सीमापार मुद्रा प्रवाहों के कारण अंतराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रभावी बैंकिग पर्यवेक्षण की कमी महसूस की गई। 1974 में जर्मनी के Bankhaus herstatt तथा अमेरिका के फ्रेंकलिन नेशनल बैंक कि विफलता ने जी – 10 के देशों के केन्द्रीय बैंकों के गवर्नरों को बैंकिग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति के गठन के लिए प्रेरित किया। 1988 में इस समिति द्वारा बासेल पूँजी समझौता (Bsael Capital Accord) सामने लाया गया।

बासेल I (BASEL I)

1981 में अमेरिका में विनियामक संस्थाओं ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी अनुपात विनिर्दिष्ट किया, परन्तु अंतरांष्ट्रीय स्तर पर 1988 में बासेल I मानदंड लागू किए जाने से पहले स्पष्ट तौर पर कोई पूँजी पर्याप्तता मानदड लागू नही था। बेसल I समझौता 1988 में जारी किया गया जो बैंक परिसंपत्ति वर्गीकरण प्रणाली द्वारा मुख्य रूप से ऋण जोखिम पर केन्दोत था। बासेल I देशो मे बैको के लिए मानकीकृत जोखिम आधारित पूंजी आवश्यकताओं को विकसित करने के लिए 1988 में देश के प्रतिनिधियों के बीच संपन्न हुआ समझौता है। बासेल I को जून 2004 म प्रकाशित नई पूँजी पर्याप्ततर ढाँचा बासेल II के साथ बदल दिया गया था ।

यह समझौता भारतीय बैंको के लिए वर्ष 1992 से लागू कर दिया गया। बैंकिग के इतिहास मे यह पहली बार हुआ था कि बैंका को अपने द्वारा दिए गए ऋणों में निहित जोखिम को देखते हुए एक निर्धारित अनुपात में न्यूनतम पूंजी बनाए रखने के लिए बाध्य किया गया। इन दिशानिर्देशों में बैंकों से यह अपेक्षा की गई कि वे अपनी जोाखिम वाली आस्तियों यानि दिए गए उधारों के कम से कम 8 प्रतिशत के बराबर प्‌जी (टियर-1 और 2) अनिवार्यत: बनाए रखें।

बासेल II (BASEL II)

बासेल I की कमियों को दूर करने के लिए बी आई एस के सदस्य देशों के बीच बैंक पर्यवेक्षण संबधी नए मानदंड अपनाने का करार वर्ष 1999 में किया गया। इसे बासेल II करार के नाम से जाना जाता है। इस करार के अनुक्रम में वर्ष 2004 में पूंजी पर्याप्तता संबधी नए दिशानिर्देश जारी किए जिनका अनुपालन वर्ष 2006 (भारत मे वर्ष 2009) तक कर लिया जाना था। भारत म बासेल II मार्च 2008 मे लागू हुआ और मार्च 2009 तक भारत के सभी अनुसूचित बैको मे बासेल II के सभी बुनियादी दृष्टिकोणो को अपना लिया गया ।

बासल II तीन स्तम्भों पर आधारित है। बासल II बैंको और पर्यवेक्षकों को विभिन्न जोखिमों का मूल्याकन करने की अनुमति देता है। जिनका सामना बैंको द्वारा किया जाता है। वह तीन स्तम्भ है -

(1) न्यूनतम प्‌जी आवश्यकता

(2) संस्था की पूंजी पर्याप्तता और आंतरिक मूल्यांकन प्रक्रिया पर्यवेक्षी समीक्षा।

(3) सुरक्षित और स्वस्थ बैंकिग प्रथाओं को प्रोत्साहित कर प्रभावी प्रकटीकरण के माध्यम से बाजार अनुशासन।

बासेल III (BASEL III)

बासेल III वर्ष 2010 में बासेल समझौते द्वारा जारी दिशानिर्देशों की तीसरी कड़ी है। इससे पूर्व बासेल I और बासेल II दिशानिर्देश जारी किये जा चुके है। बासेल III में बैंकों के लिए उसी तरह दिशानिर्देश जारी किए गए ह जैसे कि बासेल I तथा बासेल II द्वारा जारी किए गये थे। अंतर महज इतना है कि बासेल I के बाद पूँजी पर्याप्तता संबधी दिशानिर्देशों को आवश्यक्तानुसार बासेल II में थोड़ा सख्त किया गया था। उसी तरह 2008 में संपूर्ण विश्व में फैली आर्थिक संकट के मद्देनजर कुछ परिवर्तनों के साथ बासेल III को तैयार किया गया। इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं पूँजी आधार की गुणवत्ता और पारदर्शिता म सुधार किया जाना, पूँजी अपेक्षाओं को पूरा करना, पूँजी के सुरक्षित भंडार के बारे में निर्दिष्ट करना, प्रणालीगत जोखिम तथा इसकी अंत: संबद्धता से निपटना, वश्विक चलनिधि मानक प्रस्तुत करना तथा विवेकपूर्ण पूँजी वितरण नीतियाँ सुनिश्चित करना आदि।

भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बासेल III को 1 जनवरी 2013 से लागू किया जाना था तथा जिसे 31 मार्च 2018 तक पूरा करना है। परन्त् कुछ कारणवश बासेल III को भारत में 1अप्रैल 2013 को लागू किया गया।

भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India)

भारतीय स्टेट बैंक वर्तमान म सार्वजनिक क्षत्र के बैंको मे सबसे बड़ा है। भारतीय स्टेट बैंक तथा उसके सहयोगी बैंक मिलकर देश के कुल बैंकिग कारोबार का एक चौथाई से भी अधिक कारोबार संभालते ह। देश में कृषि व प्राथमिक क्षेत्रों को साख स्िवधाएं देने में भारतीय स्टेट बैंक की अहम भूमिका है।

भारतीय स्टेट बैंक का प्रादुभाव 19 वीं शताब्दी के पहले दशक में 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना के साथ हुआ। तीन साल बाद बैंक का अपना चार्टर प्राप्त हुआ और इसे 2 जनवरी 1809 को बैंक ऑफ बंगाल के रूप में पुनगठित किया गया। यह एक अद्धितीय संस्था और ब्रिटेन शासित भारत का प्रथम संयुक्त पूँजी वाला बैंक था जिसे बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया था। बैंक ऑफ बंगाल के बाद बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 15 अप्रैल 1840 को तथा बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1 जलाई 1843 को की गई। इन तीनों बैंकों का 27 जन वरी 1921 को इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में समामेलन कर दिया गया।

31 मार्च 2013 को भारतीय स्टेट बैंक और 5 सहयोगी बैंक की भारत की दूरस्थ भागों में स्थित 14816 से अधिक शाखाओं के नेटवर्क के साथ भारत का सबसे बड़ा बैंक है। जिनमें से 9851 शाखाएं ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में है। भारतीय स्टेट बैंक भारत में खुदरा आपरेशन चलाने के साथ-साथ विदेशी ग्राहकों की अंतराष्ट्रीय

जरूरता को पूरा करने के लिए 34 देशों में 180 विदेशी कार्यालय है। 32752 एटीमो के साथ भारतीय स्टेट बैंक समूह विश्व के सबसे बडे नेटवको मे से एक है।

31 मार्च 2013 को भारतीय स्टेट बैंक की प्रदत पूंजी 684.03 करोड रूपए है। भारतीय स्टेट बैंक की कुल आय 1,35,691.94 करोड रूपए और कर पश्चात लाभ 14,105.32 करोड रूपए है। भारतीय स्टेट बैंक की कुल जमा राशियां 12,02,739.57 करोड रूपए और कुल अग्रिम 10,45,616.55 करोड रूपए है। वर्ष 2012–13 को बक का कुल व्यवसाय 22,48,356.12 करोड रूपए है।

एच डी एफ सी बैंक (HDFC Bank)

सन् 1994 में हाउसिग डेवलपमेंट फाइनेस कारपोरेशन लिमिटेड को भारतीय बैंकिग में आर बी आई की उदारीकरण नोति के अन्तर्गत भारतीय रिर्जव बैंक से ''सिद्धांत रूप से'' निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करन वाला प्रथम संस्थान था। मुंबई में पंजीकृत कार्यालय के साथ, ''एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड'' के नाम से अगस्त 1994 में शामिल किया गया। एच डी एफ सी बैंक ने जनवरी 1995 में एक अनुसूचित वाणिज्य बैंक के रूप में कार्य करना प्रारम्भ किया।

31 मार्च 2013 को एच डी एफ सी बैक की 1845 शहरों में 3062 शाखाएं और 10743 एटीएम का नेटवर्क है। 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार बैंक को अधिकृत शेयर पंजी 550 करोड़ रूपये है। बैंक की कुल जमा राशियां 296,247 करोड रूपए और कुल अग्रिम 239,721 करोड रूपए ह। बक का लाभ 6,726 करोड रूपए है।

आई सी आई सी आई बैक (ICICI Bank)

भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम (ICICI) की स्थापना 5 जनवरी 1955 को भारतीय कम्पनी अधिनियम के तहत एक पब्लिक कम्पनी क रूप में गयी। इस निगम की स्थापना भारत सरकार विदेश कार्य प्रशासन विभाग, अमेरिका एवं विश्व बैंक ने भारत में निजी उघोगों के विकास एवं सहायता पहुंचाने हेतु आपसी सहमति के आधार पर की। प्रारम्भ में इसकी समस्त पूँजी को कम्पनियों, संस्थाओं तथा व्यक्तियों ने निजी रूप से धारण कर रखा था। किन्तु वर्तमान में इसकी अधिकांश अंश पूँजी सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों, जैसे–बैंकों, जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम तथा उसकी समानुषंगी कम्पनियों ने धारण कर रखी है।

निगम ऋणपत्रों के आधार पर दीर्घकालीन व मध्यकालीन ऋण देता है, निजी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों के अंशों में अभिदान करता है उसके अंशों एवं ऋणपत्रों की नई श्रखला का अन्तलेखा करता है,

बॉण्डों एवं ऋणपत्रों का क्रय करता है तथा रूपये में भुगतान होन वाले ऋणों की गारण्टी देता है। निगम की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसके द्वारा स्वीकृत ऋण राशि में विदेशी मुद्रा में मंजूर ऋणों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। 1973 के बाद से निगम ने विदेशी मुद्रा में ऋण प्राप्त करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में भी प्रवेश किया है। मुम्बई उच्च न्यायालय ने 3 अप्रैल, 1997 को विलय की मंजूरी देने के पश्चात् 1 अप्रैल, 1996 से पूर्व प्रभावी तारीख से सरकार ने नौवहन उघोग को वित्त उपलब्ध कराने वाली शिपिंग क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी ऑफ इण्डिया (SCICI) लि. का ICICI में विलय कर दिया।

आई सी आई सी आई निवेश बैंकिग, जीवन और गैर जीवन बीमा, उद्यम पूंजी और परिसंपत्ति प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी विशेष सहायकों के माध्यम से व्यापारिक व खुदरा ग्राहकों के लिए बैंकिग उत्पादों और वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराता है।

31 मार्च 2013 को आई सी आई सी आई बैंक की भारत में 3100 शाखाएं और 10481 एटीएम के नेटवर्क के साथ साथ अन्य 18 देशों में और मौजूद ह। 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार बैंक को अधिकृत शेयर पंजी 1,153.63 करोड़ रूपये है। बैंक की कुल जमा राशिया 145,341.5 करोड रूपए और कुल अग्रिम 290,249.43 करोड रूपए है।

पंजाब नैशनल बैंक (Punjab National Bank)

पंजाब का अंग्रेजो के अधीन तेजी से विकास हुआ और वर्ष 1849 मे इसे साम्राज्य मे लिए जाने के बाद इसके विकास मे और तेजी आई। इसके परिणम स्वरुप एक नया शिक्षित वर्ग उत्पन्न हुआ जिसमे गुलामी की जंजीरे तोड़कर स्वतंत्र होने की इच्छा थी। इस नवोदित वर्ग मे यह इच्छा भी पनप रही थी कि भारतीय पूँजी और ऐसे प्रबंधन से एक स्वदेशी बैंक की स्थापना की जाए जो भारतीय समाज के सभी वर्गो का प्रतिनिधित्व करता हो।

19 मई 1894 को संस्था का ज्ञापन और अंतर्नियम दायर व पंजीकृत करने के बाद बैंक का गठन भारतीय कम्पनी अधिनियम (1882 का अधिनियम VI) के तहत किया गया। 12 अप्रैल 1895 को पंजाब के प्रसिद्ध बैसाखी से एक दिन पहले बैंक कारोबार के लिए लाहौर के रावलपिंडी मे खोला गया। 31मार्च 1947 को बैक के पदाधिकारियो ने बैंक के पंजीकृत कार्यालय को लाहौर से दिल्ली स्थानान्तरित करने का निर्णय किया और इसके लिए उन्होने लाहौर उच्च न्यायलय से 20 जून 1947 को अनुमति ले ली।

31 मार्च 2013 को बैंक की देशभर में 5800 से अधिक शाखाएं तथा 6000 से अधिक एटीम है। 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार बैंक कि अधिकृत शेयर पूंजी 353 करोड़ रूपये है। बैंक की कुल जमा राशियां 3,91,560 करोड रूपए और कुल अग्रिम 3,08,725 करोड रूपए है।

.

साहित्यिक पुनर्निरीक्षण
(Review of Literature)

राष्ट्रीय स्तर पर (National Studies)

1. शालिनी अग्रवाल, रूचि और अंकुश सिंगला (2013),

''भारतीय बैंक और बासेल II ''

इस पत्र से बासेल के विस्तृत अध्ययन में सहायता करता है और पूँजी पर्याप्तता,अनर्जक परिसम्पति और कुछ चुनिंदा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शुद्ध लाभ के बीच संबन्ध पता लगाने के लिए मदद करता है। इस पत्र से पूँजी पर्याप्तता अनुपात और गैर निष्पादित परिसंपत्तिया में परिवर्तन के कारण शुद्ध लाभ पर प्रभाव की भी जाँच करता है।

2. डॉ. Kushalappa और प्रदीप आर. भंडारी (2013),

''भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वित्तीय निष्पादन मूल्याकन''

इस अध्ययन में, बैंकों का तुलनात्मक वित्तोय निष्पादन का विश्लषण करने के लिए भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच से शीर्ष के दस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को चुना गया है। जिन बैंकों को अध्ययन में शामिल किया गया है वे निम्न है भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बडोदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, कारपोरेशन बैंक, आई डी बी आई, पंजाब नेशनल बैंक सिडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इस अध्ययन का उद्देश्य चयनित बैंकों की वित्तीय निष्पादनता का विभिन्न वित्तोय मापदंडों द्वारा तुलना करना है।

3. काजल चौधरी और मोनिका शर्मा (2011),

''भारत तुलनात्मक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों का प्रदर्शन (एक तुलनात्मक अध्ययन)''

इस अध्ययन में कहा गया है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों की सेवाओं का तुलनात्मक विश्लेषण अनिवार्य हो गया था। बढ़ती प्रतिस्पर्धा, नई सूचना प्रोद्योगिकी, गिरती पसंस्करण लागतें, उत्पाद कटाव, भौगोलिक सीमायें, कम पतिबंधक सरकारी नियम आदि मुख्य कारक थे। इस पत्र मे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों एन पी ए (NPA) प्रबध का कुशलतापूर्वक विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। प्रवृति के प्रक्षेपण के लिए सांख्यिकीय उपकरण का प्रयोग किया गया है।

4. अनिल कुमार सोनी और अभय Kapre (2011),

''भारत के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों निष्पादन मूल्याकन''

इस पत्र में 2006-07 से 2010-2011 तक की अवधि के दौरान भारत मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैको के वित्तोय प्रदर्शन का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन माध्यमिक डेटा पर आधारित है। इस अध्ययन म विश्लेषणात्मक अनुसंधान डिजाइन जिसमें बैंको की शाखाओं, जमा, ऋण, निवेश और विकास दर सूचकाक की संख्या के रूप में मुख्य कार्यक्षमता संकेतक विश्लेषण किया गया है। इस अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि भारत म क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के प्रदर्शन में काफी सुधार हुआ है।

5. Dr. M. Syed इब्राहिम (2010),

''भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निष्पादन मूल्यांकन''

इस पत्र का उद्देश्य वर्ष 2005-06 में किए गए भारत के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंका के विलय / समामेलन उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने में क्या मदद मिली है की जाँच करना था। यह अध्ययन वैदानिक और प्रकृति में खोजपूर्ण है। इसमे द्वितीयक डेटा का प्रयोग किया गया है। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता ह कि भारत सरकार की ओर से शुरू कि गई एकीकरण की प्रक्रिया के बाद भारत में ग्रामीण बैंको के प्रदर्शन में काफी सुधार हुआ है।

6. डॉ. विकास चौधरी और सुमन टंडन (2010),

''भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको का निष्पादन मूल्याकन''

इस पत्र से भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको के वित्तोय प्रदर्शन का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन कुल सम्पत्ति, सम्पत्ति पर रिटर्न, इक्विटी और प्रसार अनुपात पर वापसी की गणना को गई है। इस मूल्यांकन में गैर निष्पादित परिसम्पत्ति को वृद्धिमें गिरावट को भी शामिल किया गया है। इस अध्ययन से पता चलता है कि विभिन्न चर की (CAGR)सी ए जी आर बैंक से बैंक भिन्न है।

7. कृष्ण कान्त सिंह (2003)

''भारत में वाणिज्यिक बैंक में लाभदायकता का निर्णायक विश्लेषण''

आपने अपने शोध अध्ययन में प्रकाश डाला कि बैंकों में आये-दिन होने वाली हड़तालें एवं तालाबन्दी बैंकों की क्रियात्मक कुशलता एवं लाभदायकता पर विपरोत प्रभाव डालती है, अत: बैंकों की क्रियात्मक कुशलता एवं लाभदायकता में वृद्धि करने के लिए सरकार एवं कर्मचारियों के मध्य हमेशा अनुकूल समन्वय होना चाहिए।

8. श्री निवास राव केम्बई (1989)

''वाणिज्यिक बैंकों की लाभदायकता का विश्लेषण 1976-1985''

इनके द्वारा लिखित शोधग्रन्थ में बताया गया है कि गैर-निष्पादन सम्पत्तियाँ बैंकों की लाभदायकता में कमी करती है। अत: बैंकों की लाभदायकता में वृद्धि करने के लिए गैर-निष्पादन सम्पत्तियों में कमी की जानी चाहिए।

9. सुरेश चन्द (1987)

''भारत में वाणिज्यिक बैंकों की लागत और लाभदायकता ''

आपने अपने शोध अध्ययन में लिखा है कि वाणिज्यिक बैंकां की लागत एवं लाभदायकता में धनात्मक एवं ऋणात्मक सह-सम्बन्ध पाया जाता है, अर्थात लागत के घटने-बढ़ने पर लाभदायकता भी घटती बढ़ती है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर (International Studies)

10. Savita Jha और Xiaofeng Hui (2012)

''वाणिज्यिक बैंको के वित्तीय प्रदर्शन की तुलना नेपाल का अध्ययन''

इस अध्ययन का उद्देश्य CAMEL मॉडल द्वारा नेपाल मे अलग-अलग स्वामित्व संरचित वाणिज्यिक बैंको के वित्तोय प्रदर्शन की तुलना करना था। अध्ययन के लिए नपाल के 18 वाणिज्यिक बैंका का अवधि 2005 से 2010 तक का आर्थिक रूप से विश्लेषण किया गया है। इस अध्ययन से पताा चलता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अपने समकक्ष घरेलू निजी बैंक व विदेशी स्वामित्व वाली बैंकों की तुलना मे काफी कम कुशल है।

11. डॉ. अहमद आरिफ Almazari (2012),

"Du Pont प्रणाली का प्रयोग करके जार्डन अरब बैंक का वित्तीय विश्लेषण"

यह अध्ययन 2000 से 2009 तक को अवधि के लिए जार्डन अरब बैंक मे वित्तीय प्रदर्शन को मापने के लिए जार्डन जो इक्विटी पर वापसी मांडल पर आधारित है। इस अध्ययन से पता चलता है कि अरब बैंक के वित्तीय प्रदर्शन, इक्विटी पर रिर्टन की तुलना में अधिक स्थिर है।

12. सीमा सिद्दीकुअ हाई, साफिया उमर मिन्हाज, रूही अहमद,(2011),

''बासल का कार्यान्वयनः मुद्दे, चुनौतियॉ और देश के विकास के लिए निहितार्थ''

यह पत्र पाकिस्तान में बासल क कार्यान्वयन में शामिल मुद्दे, चुनौतियों और निहिताथ र्ि की जाँच करता है। इस पत्र का मुख्य उद्देश्य बासल के कार्यान्वयन में आई समस्याओं की पहचान करता है। इस पत्र से पता चलता है कि विनियमन, पर्यवेक्षण और बाजार अनुशासन के लिए केन्द्रीय बैंकों के बीच आपसी सहयोग और सहायता की आवश्यकता है।

13. आमिर हुसैन शार, डॉ मुनीर अली शाह और डॉ जमाली (2010),

''पाकिस्तान में बैंकिग सेक्टर के प्रदर्शन का मूल्यांकनः बैंकोमीटर द्वारा ''

इस अध्ययन में बैंकोमीटर नाम का नया मांडल विकसित किया गया है जा यह गणना करने की क्षमता रखता है कि कौन सा बैंक निवेशकों, लेनदारों, खाता धारकों, और अन्य हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण है । बैंकोमीटर की सटीकता की पुष्टि करने के लिए, पाकिस्तान के प्रत्येक बैंक की 1999 से 2002 अवधि तक की शोध ान क्षमता मापी गई और इसके परिणामों की और के साथ तुलना की गई।

14. एड्यूं कोर्नफोर्ड (2006),

''बासल II की वैश्विक कार्यान्वयनः संभावनाऐं और समस्याऐं''

यह पत्र बासल के कार्यान्वयन सम्बधी संभावनाओं, परिवर्तन की वजह से शामिल जोखिम और वे तथ्य जो अतंराष्ट्रीय व्यापार में बैंकिग सेवाओं को प्रभावित कर सकते थे उनकी समीक्षाकरता है। इस अध्ययन से य ह निष्कर्ष निकलता है कि बासल बैंकों के लागत पूँजी और जोखिम नियमों के साथ साथ आर्थिक अवसरों पर भी महत्व पूर्ण प्रभाव डलता है।

प्रस्तावित शोध अध्ययन के महत्व
(Significance of Proposed Research Study)

इस प्रस्तावित शोध की सहायता से यह ज्ञात होगा कि किस प्रकार बासेल II न बैंकों की लाभदायकता और वित्तीय निष्पादन क्षमता को प्रभावित किया है। प्रस्तावित शोध अध्ययन प्रबन्धकीय एवं विनियोग सम्बन्धित निर्णय लेने में भी उपयोगी होगा क्योंकि इसके द्वारा विभिन्न विनियोग प्रस्तावों व विकल्पों का तुलनात्मक अध्ययन कर सर्वोत्तम विकल्प का चयन किया जायेगा जिससे यह पता लगाया जा सके कि बैंकों को किस विनियोग पर अधिकतम दर से प्रत्याय प्राप्त हो सके।

इस प्रस्तावित शोध में अध्ययन किया जायेगा कि किस प्रकार बासेल II ने बैका कि लाभदायकता एवं वित्तीय निष्पादन क्षमता को प्रभावित किया है। इस प्रस्तावित शोध में अध्ययन किया जायेगा कि किस प्रकार बासेल II ने बैक उपभोक्ताओ को प्रभावित किया है। इस प्रस्तावित शोध के अध्ययन द्वारा बैंकों की तरलता स्थिति व शोधन क्षमता का भी पता लगाया जायेगा ।

प्रस्तावित शोध अध्ययन क उद्देश्य
(Objectives of Proposed Research Study)

प्रस्तावित शोध अध्ययन के उद्देश्य निम्न है-

1. बासेल II मानदण्डों की रूपरेखा का अध्ययन करना।

2. चयनित बैंको की लाभदायकता तथा वित्तीय निष्पादन क्षमता का पता लगाना।

3. चयनित बैंका की लाभदायकता तथा वित्तीय निष्पादन क्षमता पर बासेल II के प्रभावों (पूर्व एवं पश्चात) का विश्लेषण करना।

4. चयनित बैंकों की लाभदायकता तथा वित्तीय निष्पादन क्षमता पर बासेल II के प्रभावों के बीच धनात्मक सह-सम्बन्ध ज्ञात करना।

5. बासेल II के प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए एक प्रभावी रूपरेखा तैयार करना।

प्रस्तावित शोध अध्ययन की शोध परिकल्पना
(Research Hypothesis of Proposed Research Study)

प्रस्तुत शोध प्रस्ताव की शोध परिकल्पनाए निम्न है-

Ho_1 निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों की लाभदायकता में कोई सार्थक अन्तर नही है।

$H1_1$ निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बकों की लाभदायकता में सार्थक अन्तर है।

Ho_2 निजो क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैको की वित्तीय निष्पादन क्षमता में कोई सार्थक अन्तर नही है।

$H1_2$ निजो क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों की वित्तीय निष्पादन क्षमता में सार्थक अन्तर है।

Ho_3 चयनित बैंकों के वित्तीय निष्पादन क्षमता पर बासेल II का प्रभाव धनात्मक नही है।

$H1_3$ चयनित बैंका के वित्तीय निष्पादन क्षमता पर बासेल II का प्रभाव धनात्मक है।

Ho_4 चयनित बैंकों के लाभदायकता पर बासेल II का प्रभाव धनात्मक नही है।

$H1_4$ चयनित बैंकों के लाभदायकता पर बासेल II का प्रभाव धनात्मक है।

Ho_5 चयनित बैंकों की लाभदायकता तथा वित्तीय निष्पादन क्षमता पर बासेल II के प्रभावो के बीच धनात्मक सह–सम्बन्ध नही है।

$H1_5$ चयनित बैंकों की लाभदायकता तथा वित्तीय निष्पादन क्षमता पर बासल II के प्रभावो के बीच धनात्मक सह–सम्बन्ध है।

प्रस्तावित शोध अध्ययन की कार्यविधि
(Methodology of the Proposed Research Study)

प्रस्तावित शोध अध्ययन में उन बैंकों का चयन किया गया है, जो 31 दिसम्बर 2006 मे सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के बैंकों में बाजार पूँजी (Market capitalization) की दृष्टि प्रथम व द्वितीय स्थान रखते है।

बैक	**क्षेत्र**	**स्थान**
भारतीय स्टेट बैंक	सार्वजनिक	1st
पंजाब नैशनल बैंक	सार्वजनिक	2nd
आई सी आई सी आई बैक	निजी	1st
एच डी एफ सी बैंक	निजी	2nd

भारतीय स्टेट बैंक तथा आईसीआईसीआई बैंक दोनों बैंक भारतीय बैंकिंग प्रणाली में अपने-अपने क्षेत्र में पूँजी की दृष्टि से प्रथम स्थान रखते है। पंजाब नैशनल बैंक और एच डी एफ सी बैंक दोनों बैंक भारतीय बैंकिंग प्रणाली में पूँजी की दृष्टि से द्वितीय स्थान रखते हैं। अत: प्रस्तावित शोध अध्ययन के कार्य क्षेत्र में SBI , PNB, HDFC तथा ICICI बैंकों को शामिल किया जायेगा।

(I) समंक (Data)

यह शोध अध्ययन पूर्ण रूप से द्वितीयक समंकों पर निर्भर करता है। शोध अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए द्वितीयक समंकों का संग्रहण विभिन्न शोध ग्रन्थों, पुस्तकों, मेग्जीनों, पत्र-पत्रिकाओं, भारतीय स्टेट बैंक, आवास विकास वित बैंक , पंजाब नैशनल बैंक तथा आईसीआईसीआई बैंक द्वारा जारी की गई वार्षिकी रिपोटों से किया जायेगा।

(II) विश्लेषण (Analysis)

भारतीय स्टेट बैंक, आवास विकास वित बैंक, पंजाब नैशनल बैंक तथा आईसीआईसीआईसीआई बैंक से प्राप्त आँकड़ो का विश्लेषण प्रबन्धकीय तकनीक (अनुपात विश्लेषण) तथा सांख्यिकीय तकनीक (सह-सम्बन्ध विश्लेषण) द्वारा किया जायेगा।

't' टेस्ट विश्लेषण ('t' Test Analysis)

प्रस्तावित शोध अध्ययन की परिकल्पनाओं की वैधता की जाँच, सांख्यिकी तकनीक 'टी' टेस्ट के आधार पर की जायेगी ।

प्रस्तावित शोध अध्ययन की अवधि (Period of Proposed Research Study)

प्रस्तावित शोध अध्ययन में वर्ष 2006-2007, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 तक (सात वर्षो) के प्रकाशित समंको का ही प्रयोग किया जायेगा।

पूर्व विश्लेषण के लिए वर्ष	2006-07, 2007-08, 2008-09
पश्चात् विश्लेषण के लिए वर्ष	2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13

उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए रूपरेखा
(Proposed action plan to achieve Objectives)

उद्देश्य	उद्देश्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया
बासेल II मानदण्डों की रूपरेखा का अध्ययन करना।	RBI और बासेल समिति द्वारा जारी बासेल II दिशानिदशो (Guideline) के अध्ययन द्वारा
चयनित बैंको की लाभदायकता तथा वित्तीय निष्पादन क्षमता का पता लगाना।	वित्तीय निष्पादन क्षमता के लिए CAMELS मांडल लाभदायकता के लिए अनुपात विश्लेषण (Ratio analysis), Growth rate, compound growth rate, Median test, Co-efficient of correlation
चयनित बैंका की लाभदायकता तथा वित्तीय निष्पादन क्षमता पर बासल II के प्रभावों (पूर्व एवं पश्चात) का विश्लेषण करना।	Du pont model (profit margin, asset turnover, equity multiplier)
चयनित बैंकों की लाभदायकता तथा वित्तीय निष्पादन क्षमता पर बासल II के प्रभावों के बीच धनात्मक सह-सम्बन्ध ज्ञात करना।	साख्यिकीय तकनीक 'सह-सम्बन्ध' (Correlation) द्वारा
बासल II के प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए एक प्रभावी रूपरेखा तैयार करना।	शोध के निष्कर्ष के आधार पर

प्रस्तावित शोध अध्ययन की विषय सूची
(Contents of Proposed Research Study)

Chapter –I	**विषय प्रवेश (Introduction)** • बैंको का इतिहास • बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेट • बासेल I • बासेल II • बासेल III • चयनित बैको का एक परिचय • शोध अध्ययन की कार्यविधि • साहित्यिक पुनर्निरीक्षण (Review of Literature)
Chapter – II	**चयनित बैंका की वित्तीय निष्पादन क्षमता और लाभदायकता का अध्ययन** • लाभदायकता का अर्थ, क्षेत्र एवं महत्व • वित्तीय निष्पादन क्षमता का अर्थ, क्षेत्र एवं महत्व • वित्तीय निष्पादन क्षमता और लाभदायकता के विश्लेषण में प्रयुक्त औजार • चयनित बैंकों की वित्तीय निष्पादन क्षमता और लाभदायकता का अध्ययन • चयनित बैंकों की वित्तीय निष्पादन क्षमता और लाभदायकता का तुलनात्मक अध्ययन

Chapter– III	**चयनित बैंकों की लाभदायकता पर बासेल II के प्रभावो का – एक विश्लेषण** • बासेल II एक परिचय • बासेल II से पूर्व चयनित बैंकों की लाभदायकता का अध्ययन – परीक्षण एवं विश्लेषण • बासेल II के पश्चात् चयनित बैंकों की लाभदायकता का अध्ययन –परीक्षण एवं विश्लेषण
Chapter– IV	**चयनित बैंका की वित्तीय निष्पादन क्षमता पर बासेल II के प्रभावो का – एक विश्लेषण** • बासेल II से पूर्व चयनित बैंकों की वित्तीय निष्पादन क्षमता का अध्ययन – परीक्षण एवं विश्लेषण • बासेल II के पश्चात् चयनित बैंकों की वित्तीय निष्पादन क्षमता का अध्ययन – परीक्षण एवं विश्लेषण
Chapter –V	**निष्कर्ष एवं सुक्षाव (Conclusions and Suggestions)**

सन्दर्भ सूची
(Reference List)

जर्नल/पत्र/पत्रिकाएें (Journal/Papers/Magzine)-

1. Times of India

2. Indian Journal of Commerce

3. Indian Journal of Accountancy

4. Business Today

5. Financial Express

6. The Hidustan Times

7. प्रतियोगिता दर्पण

8. Journal of the Institute of Chartered Accountant of India.

9. Management Accountant.

Reports-

10. Annual Report of ICICI Bank

11. Annual Report of State Bank of India

12. Annual Report of HDFC Bank

13. Annual Report of Punjab National Bank

पुस्तकें (Books)-

1. *Morse, D. (1997)*, **Management Accounting** , MC Grawhill, Newyork.

2. *R.S.N. Pillai and Bagwathi (2001)*, **Management Accounting,** Taxman, New Delhi.

3. *I. M. Pandey (2002)*, **Management Accounting (Planning and Control approach),** Vikas Publishing House (Pvt.) Ltd.

4. *Dr. Jawahar Lal (2004)*, **Accounting For Management,** Himalaya Publishing House, Mumbai.

5. *Prasanna Chandra (2004)*, **Financial Management (Theory and Practice)** , Tata McGrew Hill Publishing Co. Ltd., New Delhi.

6. *Gopalkrishnan and Sandilya (2004)*, **M.S.- Inventory Management, Text and Cases**, The MacMillan Company of India Limited, Delhi.

7. *Man Mohan & S.N. Goel (2004)*, **Principle of Management Accouting**, Sahitya Bhawan, Agra.

8. *C. McGolerick and B.Graham (2004)*, **The Interpretation of Financial Statements**, Harper & Row, London,

9. *I.M. Pandey (2004)*, **Financial Management**, Vikas Publishing, House Pvt. Ltd., Delhi.

10. *Gitman, Lawrence J. (2005)*, **Principle of Managerial Finance**, Harper & Raw Publishers, New York.

11. *N.J.Yasaswy (2005)*, **Finance for Non-Financial Executives**, Allied Publishers Pvt. Ltd., New Delhi.

12. *Ezra Solomon and John J. Pringle (2006),* **An Introduction to Financial management**, Prentice Hall Of India Pvt. Ltd., New Delhi.

13. *M.Y. Khan and* P.K. *Jain (2007)*, **Financial Management**, Tata McGrew Hill Publishing Co. Ltd., New Delhi.

14. *के. जी. गुप्ता (2007),* **प्रबन्धकीय लेखांकन,** क. जी. पब्लिकेशन, मोदीनगर।

15. *डॉ. विनोद कालरा एवं प्रो. अतुल मीतल (2008),* **प्रबन्धकीय लेखांकन,** जवाहर पब्लिकेशन्स , आगरा।

16. *Srinivasan and Murugan (2008),* **Accounting for Management**, S. Chand and Co. Ltd., New Delhi.

17. *डॉ. एस. पी. गुप्ता (2009),* **प्रबन्ध लेखांकन**, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।

18. *आर. पी. वार्ष्णेय (2009),* **उच्चतर सांख्यिकी**, जवाहर पब्लिकेशन, आगरा।

19. *अग्रवाल एवं मेहता (2009),* **प्रबन्धकीय लेखाविधि**, साहित्य भवन, आगरा।

20. *डॉ. ए. के. गर्ग (2010),* **प्रबन्धकीय लेखांकन**, स्वाती पब्लिकेशन, बुलन्दशहर।

21. *अग्रवाल एवं अग्रवाल (2010),* **प्रबन्धकीय लेखांकन** , रमेश बुक डिपो, जयपुर।

22. *डॉ. के. एल. गुप्ता (2010),* **प्रबन्धकीय लेखाविधि**, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा।

23. *डॉ. एल. एन. कोली ,* **प्रबन्ध लेखांकन,** वाई के पब्लिकेशन, आगरा।

25. *डॉ. एल. एन. कोली,* **रिसर्च मेथोड्लौजी**, वाई के पब्लिकेशन, आगरा।

***Website*: -**

1. www.managerwise.com
2. www.statebankofindia.com
3. www.icicibank.com
4. www.question.com
5.www.indianjournalofcommerce.com
6. www.Money.com
7. www.Indiabull.com
8. www.pnb.com
9. www.hdfcbank.com

प्रो. प्रमोद कुमार — **विभागाध्यक्ष/संकाय प्रमुख**

डॉ. लक्ष्मीनारायण कोली — **निर्देशक**

अमित सिंह — **शोध छात्र**

लेखा एवं विधि विभाग
वाणिज्य संकाय, दयालबाग शिक्षण संस्थान
(डीम्ड विश्वविद्यालय)
आगरा–5